

(67)

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम— जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मालकोट-कालीमाटी-सेरा-तिवाखर्क मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 3.00 किमी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम —————

तहसील गैरसैण, जिला—चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मालकोट-कालीमाटी परियोजना के निर्माण हेतु 0.070 हे० आरक्षित वन भूमि 1.085 हे० सिविल सोयम भूमि 0.180 वन पंचायत भूमि ——— हे० अर्थात् कुल ——— हे० वन भूमि का लगे निजी विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कालीमाटी द्वारा दिनांक 05/02/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कालीमाटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लगे निजी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

मुहर सहित

ह०/-

ग्राम प्रधान/संरक्षक

मुहर सहित

68

प्रारूप-30.4

दिनांक 05/01/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कालीमारी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गिलिहिट्टे विष्णु अण्णाप्पु ग्राम मुखिया	गिलिहिट्टे
2	खुरेड मिा विष्णु ग्राम मुखिया	खुरेड
3	कान्त सिंह विष्णु	कान्त सिंह
4	मल्लारि सिंह विष्णु	मल्लारि सिंह
5	गिलिहिट्टे विष्णु	गिलिहिट्टे
6	गिलिहिट्टे विष्णु	गिलिहिट्टे
7	गिलिहिट्टे विष्णु	गिलिहिट्टे
8	गिलिहिट्टे विष्णु	गिलिहिट्टे
9	गिलिहिट्टे विष्णु	गिलिहिट्टे
10	अवतार सिंह	अवतार सिंह
11	वीरे-रावटे	वीरे-रावटे
12	दीवान सिंह	दीवान सिंह
13	अवतार सिंह	अवतार सिंह

80/-

ग्राम प्रधान



Dr. Dinkar
S.D.O. - Ludhiana

Dr. Dinkar
S.D.O. - Ludhiana

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मालकोट- कालीमाटी - सेरा - तिवाखर्क मोटर मार्ग का निर्माण । (लम्बाई 3.00 किमी)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - मालकोट
तहसील-गैरसैण, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मालकोट -कालीमाटी - सेरा -परियोजना के निर्माण हेतु (0.070 हे० आरक्षित वन भूमि ,1.085 हे० सिविल सोयम भूमि 0.472 हे० वन पंचायत भूमि - हे०) अर्थात् कुल 1.627 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत -मालकोट द्वारा दिनांक ०७/१२/२०१५ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम- मालकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

(उत्प्रेषण पत्र लिख)
ग्राम सचिव
ग्राम विकास अधिकारी
मुहर सहित मालकोट
क्षेत्र - गैरसैण (चमोली)
वि.ख. - गैरसैण (चमोली)



ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारूप-30.4

दिनांक 04/11/15 को ग्राम सभा के सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायतमालकोट.....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	केदार सिंह 5/0 श्री आलम सिंह केरत	1/11
②	शेखर लाल सिंह 5/0 वागछिड़ रोवो	5/11 2011
③	उमेश सिंह 5/0 कल्याण सिंह	5/11
④	आनन्द सिंह 5/0 केदार सिंह	आनन्द सिंह
5	गजेंद्र सिंह 5/0 वरुण सिंह	गजेंद्र सिंह
6	मान सिंह 5/0 हरमन सिंह	मान सिंह
7	बुध सिंह 5/0 आनन्द सिंह	बुध सिंह
8	भारत सिंह 5/0 बलवीर सिंह	Bh
9	दलीप सिंह 5/0 पंचम सिंह	दलीप सिंह
10	रघुवीर सिंह 5/0 दिवान सिंह	रघुवीर सिंह
11	बलवीर सिंह 5/0 रतन सिंह	बलवीर सिंह

2018
(उमेश चन्द्र सिंह)
ग्राम विकास अधिकारी
क्षेत्र - ...मालकोट...
वि.ख. - गैरसैण (पनौली)



प्रारूप-30.2

परियोजना विवरण :- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में भालकोट-कालीमाटी-सेरा से तिवाखरक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.627 हे० का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.000 कि०मी०।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गैरसैण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, गैरसैण

0-070 उपर्युक्त संकेतक पत्रिका के अन्तर्गत उत्तमपंचायत बागोबादी विधान के जोड़े हुए
(~~0-071~~ 80 आरक्षित वन भूमि 0-472 80 सिविल एवं सौधम वन भूमि 0-085 80 वन पहायत भूमि अर्थात् कुल
+ 0-077 80 वन भूमि) का लेन-निर्दिष्ट मैरुठो प्रयोक्ता एजन्सी के तहत में हस्ताक्षरित किये जाने हेतु
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत समुदायों (वन अधिकारों की सम्पत्ति) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपर्युक्त
हस्तक्षेप समिति, (गहरील मैरुठो) की दिनांक 08-02-15 को सम्बन्ध बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक की 12-12-2018
उप निदेशिकाएँ एवं अध्यास उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में
माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----|--------------------------|----------------------------|---------------|
| 1- | श्री किशन सिंह नेगी | उपविभागाधिकारी | अन्यथा |
| 2- | श्री सुन्दर लाल | उप प्रशासीय सहायिका | सदस्य |
| 3- | श्री सुन्दर लाल | सहायक सभासद कल्याण अधिकारी | सदस्य / सदस्य |
| 4- | श्री श्री श्री श्री श्री | श्री श्री श्री श्री श्री | सदस्य |
| 5- | श्री श्री श्री श्री श्री | श्री श्री श्री श्री श्री | सदस्य |

अनुमति से बैठक की व्यवस्था प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जेकराद गवर्नरी के निवासकाय और ऐन में आने के बाद किसी तरह निवास करने जोरदार परिचयजाना हेतु 16.02.80 वन भूमि

प्रयोगशाला एवं नदी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाते हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला उल्लिखित नहीं है। उससे भूमि का संबंधित ग्राम समा द्वारा सर्वेक्षणों से पारित प्रस्तावों के अन्तर्गत पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यागमन की अनुमति दी गई है।

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं संसदसभ्यी नियम 2008 को प्राधिकारण की स्थिति करते हुए जानकारी के माध्यम से सर्वसभ्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी आवेदक को बाबा/आदिवन वन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा जमापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपलब्ध सूत्रीय वन अधिकार समिति द्वारा जमापत्ति जारी की जा सकती है।

विशेष में सर्वसम्मति से उपस्थित 1885 एक्ट के अन्तर्गत प्रोविजेंट प्रावधानों के
परिचालन के निर्माण हेतु 1827 एड वन भूमि अधिनियम प्रोविजेंट एजेंसी की जगह में
स्वयं प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर अध्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

१. संविधान
 २. संविधान
 ३. संविधान
 ४. संविधान

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, जिला न्यायाधीश एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी, जयपुर
उपखण्ड स्तरीय कार्य निदेशिका संख्या २२००/२०१८
गहरीय
जयपुर

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रयोजनों पर सूचना/अभिलेख सलग्न किये जाने हैं।)

FORM-I
(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No.---

Dated 15.03.15

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3 August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5 February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1 627 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gairsain for construction of Malkot-Kalimati-Saira-Tiwakhark motor road in Chamoli district falls within jurisdiction of Kalimati, Saira and Tiwakhark villages in Gairsain tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1 627 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रा.प-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar I.A.S deputy commissioner, Chamoli on dated 15-02-15, at time 11:00 AM at Gopeshwar, in which application claiming rights in ~~Chamoli~~ area measuring 1.627 hect for the construction of Malkot-Kalimati-Satra-Tiwakhark motor road forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Kalimati-Satra-Tiwakhark sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated: 15-02-15


Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee